

II. Notification of Ministry of Labour.

III. Notifications of Ministry of Coal,

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : Madam, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(i) (a) Seventy-third Annual Report and Accounts of the Singareni Collieries Company Limited, Kotha-gudem (Andhra Pradesh) for the year 1993-94, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

(Placed in Library. See No. LT/6470/94)

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Coal India Limited, Calcutta (Volumes I and II), for the year 1993-94, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

(Placed in Library. See No. LT/6639/94)

II. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Labour (Directorate General of Employment and Training) Notification G.S.R. No. 432, "dated the 20th August, 1994, publishing the Apprenticeship (Amendment) Rules 1994, under sub-section (3) of section 37 of the Apprentices Act, 1961.

(Placed in Library See No. LT/6657/94).

III. (a) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Coal Notification G.S.R. No. 743(E), dated the 11th October, 1994, publishing the revised rates of the various grades of coal, under subsection (I) of section 28 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957.

(Placed in Library. See No. LT/6460/94).

(b) A copy (in English and Hindi) of the following Notifications on the Ministry of Coal, under section 7A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 :—

(i) GSR No. 390, dated the 6th August, 1994, publishing the Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1994.

(ii) GSR No. 391, dated the 6th August, 1994, publishing the Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1994.

(iii) GSR No. 392, dated the 6th August, 1994, publishing the Rajasthan Coal Mines Provident Fund (Amendment) Scheme, 1994.

(Placed in Library. See No. LT/6469/94).

Reports of the Public Accounts Committee

श्री जिलोकानाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं आपकी आज्ञा से दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा के संबंध में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी लोक लेखा समिति के छिहतरवें प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

Pe. TADA

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Biplab Dasgupta—he is not present

श्री राज बख्शर (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदया, मैं "टाडा" के बारे में जो गलत इन्फार्मेशन दी गयी है उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ।

उपसभापति : "टाडा" का तो हो गया था।

श्री राज बख्शर : लेकिन गृह मंत्री का यह कहना था कि सदन में कुछ संसद सदस्यों ने "टाडा" के बंटियों के बारे में कुछ गलत आंकड़े दिये हैं,* बोला है। ये मेरे पास दो अखबार हैं, इनकी बिना पर मैं यह बात कहना चाहूंगा कि (व्यवधान)

SYED SIBTEY RAZI: (UTTAR PRADESH): Madam, I have an objection because an unparliamentary word has been used against the Leader of the House. Nobody can say that somebody is saying *. This is unparliamentary and should be removed from the record.

श्री राज बख्शर : देखिये अगर अनपार्लियामेंटरी है... (व्यवधान) मैडम, देखिये, आज जो अनपार्लियामेंटरी लफ्जों की बात आ रही है लेकिन वहाँ पर लोग मर रहे हैं, उनका खून... (व्यवधान) हो रहा है। यह बात आ के सभ में नहीं आ रही है। अनपार्लियामेंटरी शब्दों पर आप जा रहे हैं... (व्यवधान)

SYED SABTEY RAZI I am very sorry. I am not objecting to his breaking. My point is: we don't use unparliamentary words against the Leader of the House. I want to say this... (Interruptions)...

श्री राज बख्शर : आपको शब्दों की पड़ी है, वहाँ पर आदमियों की जानें जा रही हैं, आदमों मरे जा रहे हैं, भूख से लड़प रहे हैं। आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिये, अगर यह ऐसा शब्द है तो वापस ले लेता हूँ... (व्यवधान) लेकिन इंसानों को बात सुनिये... (व्यवधान)

♦Expunged as ordered by the Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Let me handle the situation. Just-aminute... (Interruptions).

श्री राज बख्शर : असत्य कहा माननीय सदस्य ने। इस सदन में संसद सदस्यों ने असत्य बोला है। मैं कहता हूँ कि यह पता करना है कि असत्य, उपसभापति महोदया किसने बोला है (व्यवधान...)

उपसभापति: बात होने जाने दीजिये।

श्री राज बख्शर : माननीय उपसभापति महोदया, यह प्रिविलेज का मोशन है... (व्यवधान)

श्री वीरेन जे. साह महाराष्ट्र) : सही बात कर रहे हैं। वैसे कोई बात हा तो आप रिकार्ड से निकाल सकती हैं बाद में। अभी आप रिकार्ड पर जाने दीजिये... (व्यवधान)

उपसभापति : आप एक मिनट जरा बैठेंगे, कन्फ्यूजन होता है।

What I said was that the word should not go on record.

जो अनपार्लियामेंटरी बर्ड है वह नहीं आयेगा। हम ऐसी कोई बड़ी बात... (व्यवधान)

श्री राज बख्शर: सत्य से दूर है, इसको ले लीजिये। धन्यवाद। मैं अपने सीनियर की कद्र करत हूँ जो मझे शब्दों की माला सिखा रहे हैं!

उपसभापति महोदया, मैं जानना चाहता हूँ कि गृह मंत्री बतायें कि वह कौन-सा संसद सदस्य है।

उपसभापति : किसके बारे में हो रहा है... (व्यवधान)

श्री राज बख्शर: जिसने ये गलत बातें कहकर भारत के गृह मंत्री को परेशान किया है कि उन्हें हर जगह, दर-दर घूमकर यह कहना पड़ रहा है कि दो आंकड़े जो सदन को दिये गये हैं वे असत्य हैं।

उपसभापति महोदय, आज पूरा राष्ट्र जानता है कि संसद सदस्य असत्य है या गृह मंत्री असत्य है। दोनों में से जो भी असत्य है उसमें संसद की अविश्वास होती है। प्रिविलेज होता है, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ।

यह क्या बिडम्बना है गृह मंत्री के कहे अनुसार कि 90 करोड़ की आबादी में 6,304 लोगों के लिये हमारे गृह मंत्री साहब को एक नया कानून डूटना पड़ रहा है जिसका नाम "टाडा" है। मेरे जैसा नया आदमी आप ही पंचायत में त्रिकुल बनपड़ है। उसको शब्द भी नहीं आते हैं, मैं आप की सदन से गजारिज करता हूँ, अगर यह मुल्क "टाडा" में ही चलता है तो मेट्रबानी करके यह सदन, बाकी सारे कानूनों का रद्द करके, खारिज करके सिर्फ "टाडा" को इस देश में खगाये। ताकि यह देश सुचारु रूप से चल सके। माननीया उपसभापति महोदय: (व्यवधान)

उपसभापति : राज बब्बर जी, एक मिनट। ... (व्यवधान)

श्री राज बब्बर : महोदय, मैं इस बयान से ... (व्यवधान)

उपसभापति : एक मिनट। आपने यह मसला उठाया है। ... (व्यवधान)

श्री राज बब्बर : होम मिनिस्टर साहब का बयान है। टाडा में क्यों ?

Because extraordinary conditions prevail in the country.

न पूछना चाहता हूँ गृह मंत्री महोदय यह बताये कि एक्स्ट्रा आर्डिनरी कंडीशंस क्या होती हैं? मैं अंग्रेजी में नहीं समझता। मुझे एक्स्ट्रा आर्डिनरी कंडीशंस के बारे में समझाया जाये। इसका अनुवाद करके बताया जाये। ... (व्यवधान)

उपसभापति : मि० राज बब्बर, जस्ट ए मिनट प्लीज।

श्री राज बब्बर : यह एक्स्ट्रा आर्डिनरी कंडीशंस आज से दो साल पहले थीं, आज मैं तीन साल पहले थीं या आज हैं, कृपया

विस्तार से गृह मंत्री जी इसका अनुवाद करके बतायें। दूसरा शब्द यह कहते हैं कि इसका "मिसयूज" हुआ है। डिनार्ड नहीं करते। ... (व्यवधान)

उपसभापति : राज बब्बर जी, वन मिनट प्लीज। बैठिये। एक मिनट रुकिये। ... (व्यवधान)

श्री राज बब्बर : मैं पूछता हूँ कि "मिसयूज" का मतलब क्या है। ... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is he doing?

श्री राज बब्बर : अगर गृह मंत्री का यह कहना है, अगर यह कहते हैं कि मिसयूज हुआ है तो क्या ... (व्यवधान) इनके बखतरबन्द लोगों को किसने यह छूट दी थी? ... (व्यवधान)

उपसभापति : मि० राज बब्बर, वन मिनट प्लीज बैठिये। बैठ जाइये। ... (व्यवधान) एक मिनट बैठिये।

श्री राज बब्बर : यह सवाल जो है ... (व्यवधान) उनकी सनस में आना चाहिये ... (व्यवधान) यह सवाल गृह मंत्री का है, सदन का नहीं है, यह पूरे देश का सवाल है (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raj Babbar, one minute. *Baithiye (Interruptions)* Please, one minute. *(Interruptions)* Let me handle it. Let me understand what his problem is. *(Interruptions)* Sit down please. I will not allow things to go on record if you don't listen to me. I will not allow anything to go on record.

श्री राज बब्बर : *

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. It is not going on record.

श्री राज बब्बर : *

*Not recorded.

THE DEPUTY CHAIRMAN :
My mike is not working again.
(Interruptions) It is not working. I can't
hear him. (Interruptions)

श्री राज बब्बर : * .

THI; DEPUTY CHAIRMAN :-
Buthiye, Mr. Raj Babbar, please sit down.
(Interruptions) Please sit down.
(Interruptions) Nothing is going on record
now.

SHRI RAAJ BABBAR: *

THE DEPUTY CHAIRMAN: I said
please sit down. I won't allow it on record.

SHRI RAAJ BABBAR: * .

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. I am
not allowing. I can't allow disorder in the
House.

SHRI RAAJ BABBAR: * . .

THI; DEPUTY CHAIRMAN: No. I am
not permitting it. Nothing is going on record.

SHRI RAAJ BABBAR: *

THE DEPUTY CHAIRMAN:
No. Nothing is going on record.

SHRI RAAJ BABBAR: £

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raj
Babbar, please sit down.

SHRI RAAJ BABBAR: *

THE DEPUTY CHAIRMAN:
Sit down. (Interruptions) You sit down.

SHRI RAAJ BABBAR: *

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not
allowing. . (Interruptions) No. I am not
allowing.

SHRI RAAJ BABBAR: *

THE DEPUTY CHAIRMAN : No.
Please sit down. I am not allowing
it.

SHRI RAAJ BABBAR: i

THE DEPUTY CHAIRMAN : No. I
will not allow. Nothing is going on record
and it should not be permitted.

SHRI RAAJ BABBAR: j

THE DEPUTY CHAIRMAN:
No. I am not allowing. I am not
allowing. (Interruptions) Nothing
is going on record and it should not
be reported.....

SHRI RAAJ BABBAR: *

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. I is not
going. I am not allowing. Please sit down,

SHRI RAAJ BABBAR: *

THE DEPUTY CHAIRMAN: what are
you raising? I don't understand it.

SHRI RAAJ BABBAR: *

THE DEPUTY CHAIRMAN:
No. I can't allow like this.

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) :
मैडम, ऐसा है, एक मिनट मुन ले। कृपया
बात को सुनिये। आप इनका दर्द नहीं
समझते। इन लोगों ने पिछले दिनों टाडा
का सवाल उठाया। माननीय गृह मंत्री
जी, जो इस सदन के नेता हैं, उन्होंने
एक फिगर दी थी कि देश में इतने लोग
टाडा में बन्द हैं। कल-परसों का रंगनाथ
मिश्र का बयान है, जो इन से चौगुना नम्बर
दे देता है। तो लगता है या तो माननीय
गृह मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।
ता यह दर्द जो लोग सवाल उठाये थे या
देश के लोगों के मन में है कि हम राज्य
सभा में बहस कर रहे हैं कि गृह मंत्री
जी ने एक फिगर दी है कि देश भर में इतने

लोग शब्द में बन्द हैं, तो रंगनाथ मिश्रा कोई छोटी हैसियत के आदमी नहीं हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। इस समय बहुत बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं। वह अपनी हैसियत में कहते हैं कि चांगुना नंबर है 28 हजार के करीब। तो इस पर सदन का यह स्फूर्तिकरण होना चाहिये। या फिर गृह मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन जाना चाहिये... (अव्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Jagechji, please sit down. Let me handle it (Interruptions). You please keep quiet.

If you feel that in your opinion what is being said on the floor of the House by the Home Minister is not correct, you are free to move a privilege motion. But, I cannot allow another discussion on it. That is a different matter because the matter was already raised. I have been shown a paper where Chairman Sahib has rejected it. He said that once the matter was raised on Friday, it cannot be raised again on the floor of the House. So, if you feel that there is any discrepancy, you move privilege motion and let the Chairman decide about it. Okay. Now, I have to call Mr. Dr. Biplob Dasgupta.

RE: SETTLEMENT OF BABRI MASJID ISSUE

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Madam, I am raising the issue of Babri Masjid. Last week, the Home Minister told us that in the light of the decision of the Supreme Court, there are now two options available. The first option is to go for negotiations and the second option is to take advantage of Article 138 of the Constitution and refer all the cases which are now pending in various courts in U. P. to the Supreme Court. My feeling is that these two options are not mutually exclusive. It is possible to continue discussions and negotiations, whatever is possible; at the same time, also refer this issue to the Supreme Court for settlement.

And if that is done, then, I would expect different political parties to take a position that whatever decision comes out of the Supreme Court would be respected by all the political parties. If that is not done, then there is no way that this very important issue can be resolved. What I find worrying is this, while the Home Minister made such a categorical statement, all the preparations are being made for setting up a trust for the construction of a Ram Temple by the Government. On this, the Godmen have been divided into two factions—one is the BJP—led government and the others are the Congress—led Godmen. All kinds of parleys are going on and with the Prime Minister touching the feet of "Gurus" and all that is completely tarnishing the secular image of our country. My point is this, if the Government is really interested in resolving the issue—then this is not the way that it should be done. Certainly, the matter should be referred to the Supreme Court and let the Supreme Court take a position on this and we should not pollute the atmosphere of the country by involving all kinds of Godmen and dividing them into groups got into and intrigues and all that. I would also like to make a point.

While the discussion is going on that, unfortunately, the promise which was made by the Prime Minister on the night of 6th December that the Babri Masjid which had been pulled down would be reconstructed at the same site, that promise, it seems, has been completely forgotten. There is an ominous silence on the part of the Government on the particular pledge—the pledge was given very categorically and it was broadcast over the television. Unfortunately, not a single word is coming from the Government or from any quarter on this particular issue as to what is going to happen at that place, whether the Government is interested in keeping that pledge or not. I would also like to have a categorical assurance from the Government on this issue.